सांध्य दैनिक 4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 12 ● अंक 225 पृष्ठः 8 ● लखनऊ, बुधवार 23 सितम्बर, 2026

मूल्य ₹ 3/-

जो छोटी-छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
-अल्बर्ट आइंस्टीन

टी20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने टॉप... 7 | पंजाब में विस चुनाव से पहले गरमाई... 3 | चुनाव आयुक्त सही से नहीं कर... 2

एसआईआर विवाद देश में सियासी इमजरजेंसी जैसे हालात

चुनाव आयोग में बहुमत नहीं तो फैसले कैसे वैध : कपिल सिब्बल

» एसआईआर पर विद्रोह चुनाव आयोग के घर में ही फूटी बगावत की चिंगारी

» बाहर विपक्ष का हल्लाबोल अंदर असहमति की गूंज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि सिर्फ देश की जनता ही नहीं देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था चुनाव आयोग भी पिछले कई महीनों से बेचैनी में था। जिस चुनाव आयोग के फैसले से देश का लोकतंत्र चलता है जिस संस्था के हाथ में करोड़ों मतदाताओं की किस्मत और वोटर लिस्ट की चाबी होती है उसी तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर एसआईआर को लेकर ऐसी हलचल मची है कि अब मामला एटम बम की तरह फूटा है और पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है।

दस महीने, दस महीने तक सवाल, दस महीने तक आपत्तियां और अब सामने आया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई। कुछ आपत्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उन फैसलों को लेकर थीं जिनके बारे में दोनों का कहना था कि उन्हें जानकारी या मंजूरी नहीं थी। एक मामले में कार्रवाई को अनधिकृत और गैरकानूनी तक बताया गया। अब जरा इस तस्वीर को समझते हैं। चुनाव आयोग में तीन सदस्य है एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दूसरी तरफ दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी और दोनों की तरफ से बार बार लिखित आपत्तियों का दर्ज करना तो सवाल उठना लाजिमी है कि क्या चुनाव आयोग के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा था। क्या एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई थी या फिर वोटर लिस्ट से आगे बढ़कर मामला अब वोटर के अधिकार और चुनावी व्यवस्था के नियंत्रण तक पहुंच गया है। जिस प्रकार के आरोप सपूर्ण विपक्ष पहले लगा चुका है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार हाईजैक कर ली गयी।

> "10 महीने और आयुक्तों के 14 सवालों से पूरे सिस्टम की भूमिका संदिग्ध!"

आपत्तियां छोटी मोटी नहीं है

चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां कोई छोटी-मोटी फाइलों पर नहीं थीं नए वोटर कौन होंगे किसका नाम वोटर लिस्ट से हटेगा किसका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा फार्म क्यों बदला गया वोटर डाटा किसके नियंत्रण में रहेगा और सबसे बड़ा सवाल जमीन पर वोटर लिस्ट तैयार करने वाले अधिकारियों की ताकत क्या धीरे धीरे दिल्ली के केंद्रीय सिस्टम के हाथ में जा रही है यानी जिस एसआईआर को को लेकर सड़क से संसद और अदालत तक सवाल उठ रहे थे अब उसकी तपिश चुनाव आयोग के अंदर तक पहुंच चुकी है। फार्म 6 का मामला तो और भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। नए वोटर को भरने वाले इस वैधानिक फॉर्म में एसआईआर से जुड़ा नया सवाल जोड़े जाने पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई। रिकॉर्ड पर इसे अनधिकृत और गैरकानूनी बताते हुए इसे हटाने की मांग तक हुई।

फिर आया वोटर डाटा का सवाल

वह डाटा जिसके आधार पर तय होना है कि कौन वोट देगा और किसका नाम सूची में रहेगा। दोनों चुनाव आयुक्तों ने डेटा के क्रमिक केंद्रीकरण को लेकर चिंता जताई। मामला इतना गंभीर था कि आईटी व्यवस्था और चुनावी रोल से जुड़े अधिकारों को लेकर कैबिनेट सचिव तक पत्र भेजे गए। गोवा में 97 मतदाताओं का मामला भी सामने आया जहां स्थानीय अधिकारी पात्रता से संतुष्ट थे लेकिन सॉफ्टवेयर के स्तर पर उनकी स्वीकृति दर्ज नहीं हो पा रही थी। अब बताइए यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या लोकतंत्र के दरवाजे पर लगा ऐसा ताला जिसकी चाबी सिस्टम के पास चली जाए उधर देश में एसआईआर को लेकर पहले से बवाल है। बिहार से शुरू हुई प्रक्रिया 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक पहुंची और ड्राफ्ट रोल में 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने की बात सामने आई। दिल्ली में लाखों मतदाताओं को नोटिस दिए गए। अदालत में प्रक्रिया पर सवाल उठे। और अब उसी एसआईआर पर केंद्र में बैठे चुनाव आयोग के भीतर से दो सदस्यों की लगातार आपत्तियां सामने आ गई हैं। मतलब आग बाहर थी ही अब धुआं घर के भीतर से भी दिखाई दे रहा है। इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई जांच और एसआईआर पर रोक या वापसी जैसी मांगें उठाई हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो एसआईआर रद्द करने और पुराने वोटर रोल बहाल करने की मांग तक कर दी है।

'एक व्यक्ति कैसे ले सकता है महत्वपूर्ण फैसले'

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का मामला सामने आने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला। उनहोंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज्ञानेश कुमार के साथ आयोग के बाकी दो सदस्यों का बहुमत नहीं था इसके बावजूद फैसले कैसे लिए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तीन सदस्यों की संस्था है और महत्वपूर्ण फैसले बहुमत से होने चाहिए उनके मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में 14 बार फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर दो आयुक्त किसी निर्णय के खिलाफ हैं तो उसे केवल एक सदस्य के स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि फार्म 6 में बदलाव से लेकर एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों तक में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल निलंबित करने एसआईआर प्रक्रिया रोकने और हाल में हुए बिहार तथा अन्य चुनावों को लेकर भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत अब तक करोड़ों नाम प्रभावित हुए हैं और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। उनहोंने कहा कि चुनाव आयोग तीन सदस्यों की संस्था है अगर दो सदस्य किसी फैसले पर आपत्ति दर्ज करते हैं और फिर भी फैसला लागू होता है तो आखिर उस फैसले की वैधानिक और संस्थागत जवाबदेही किसकी होगी?

चुनाव आयुक्त सही से नहीं कर पा रहे काम : अखिलेश यादव

» चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों पर सपा प्रमुख चिंतित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली/लखनऊ। चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयुक्त अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कीं।

एक ही दिन में अधिकतम चार बार आपत्ति दर्ज की गई। ये आपत्तियां उन फैसलों और निर्देशों को लेकर थीं, जो उनके मुताबिक, उनकी सहमति के बिना जारी किए गए। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं।

सपा कार्यालय में का नया पोस्टर, हनुमान जी से आशीर्वाद लेते दिखे सपा प्रमुख

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव का एक नया पोस्टर चर्चा में है। इस पोस्टर में अखिलेश को भगवान हनुमान से आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया है। यह पोस्टर ऐसे समय सामने आया है, जब सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी चुनावों को ''बाबर और बजरंग'' के बीच का चुनाव बताया था। सीएम आदित्यनाथ ने मेरठ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यक्रम को संबोधित

करते हुए कहा था, ''बाबर के अनुयायियों को केवल बजरंग के भक्त ही जवाब दे सकते हैं। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को हाथ जोड़कर भगवान हनुमान के सामने बैठे हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया है। पोस्टर पर ''विजय भवः'' संदेश लिखा है, जिसे सपा की ओर से भाजपा की आक्रामक राजनीति के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, रविवार व सोमवार को लखनऊ, उन्नाव, इटावा, सीतापुर, बरेली, मेरठ, आजमगढ़ और गाजीपुर समेत कई जिलों में सपा प्रमुख को निशाना बनाने वाले पोस्टर सामने आए थे।

लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात

कहा कि एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं।

बिहार में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं सीएम इस्तीफा दें : तेजस्वी

» जमुई मामले पर राजद को एनडीए सरकार पर हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जमुई में दो नाबालिग छात्राओं के साथ हुई घटना को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि वीडियो से पता चलता है कि राज्य में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। यादव ने चौधरी के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुंगेर में किसी को कोई नुकसान पहुँचता है, तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।

यादव ने कहा कि बिहार सरकार की पूरे देश में आलोचना हो रही है। चौधरी की पुरानी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने खुद पहले कहा था, मुंगेर जाइए... अगर किसी के साथ कुछ होता है या किसी को नुकसान पहुँचता है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा कि आज यह वीडियो दिखाता है कि बिहार में महिलाएं और लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं... चाहे दिन हो या रात, घर हो या सड़क, कॉलेज हो या स्कूल, या फिर अस्पताल। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वह बेहद शर्मनाक है। इसके बाद यादव ने चौधरी को सीधे चुनौती दी कि वे अपने पहले दिए गए बयान पर कायम रहें। उन्होंने कहा कि अगर सम्राट चौधरी अपनी बात पर कायम हैं, तो हिम्मत हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे अपनी कही बात पर कायम नहीं रह सकते, तो ऐसे डींगें हांकने वाले मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। यादव ने उस वीडियो का भी जिक्र किया और सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आप सभी ने वीडियो देखा होगा, और दुख की बात यह है कि सत्ताधारी गठबंधन के लोग इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमुई का एक वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आई। वीडियो में कुछ लोगों का एक ग्रुप दो नाबालिग छात्रों को परेशान करता हुआ दिख रहा था। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 19 सितंबर को हुई थी, जब 10वीं क्लास की एक छात्रा और उसका एक लड़का दोस्त कोचिंग क्लास के बाद उस इलाके में गए थे। वे टू-व्हीलर से लौट रहे थे, तभी कथित तौर पर लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने बताया कि बाद में पीड़ितों की पहचान की गई और उनके बयान दर्ज किए गए।

बीजेपी हर चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है : शिवपाल

» राजभर और मसूद से बोले सपा नेता पर बोले - आप कितने प्रदेश बनाएंगे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बुधवार (22 सितंबर) को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चाहती है कि साल 27 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हिंदू-मुस्लिम का मुकाबला बन जाए। आजमगढ़ से देवरिया जाते समय शिवपाल यादव ने कहा, सपा इससे विचलित नहीं होगी और विकास तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर ही टिकी रहेगी। बीजेपी हर चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, लेकिन हम इससे विचलित नहीं होंगे।

शिवपाल यादव ने आगे कहा कि कि सपा पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती रहेगी। बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वालों को 27 में सबक सिखाया जाना चाहिए. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बुलडोजर की कार्रवाई पर यादव ने आरोप लगाया कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को निशाना बना रही है। ऐसी कार्रवाई संविधान को कुचलने और कुछ समुदायों को पिछड़ा बनाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, यूपी के बंटवारे की चर्चाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर और इमरान मसूद ने विभाजन का समर्थन किया। इन दोनों को जवाब देते हुए

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिम यूपी भी बनेगा। यूपी को छोटे-छोटा राज्यों में बांटकर किसका फायदा होगा? आप कितने प्रदेश बनाएंगे? अगर कोई प्रदेश छोटा हो जाता है तो उसका महत्व घट जाता है। जहां-जहां छोटे प्रदेश बने हैं, वहां उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। पहले बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म करिए। विपक्ष को पीड़ितों से मिलने से रोककर सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है।

बसपा की बैठक में पहुंचे ईशान आनंद

» मायावती ने संयोजक बनाया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आयोजित बसपा की अहम बैठक में बुधवार को ईशान आनंद भी पहुंचे। बैठक से पहले उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पार्टी में हालिया बदलावों के बीच ईशान को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है। मायावती ने हाल ही में उन्हें पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देने की बात कही थी। आज उन्हें बैठक में संयोजक बनाने का ऐलान किया गया।

बता दें कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष शामिल रहे। इसमें मायावती चुनाव की जमीनी तैयारियों और प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा की। साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया। इसके अलावा सभी राज्यों से संगठन से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी, जिसके आधार पर आगे के निर्देश दिए। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बुधवार को होने वाली बैठक में मायावती के संबोधन पर नजरें हैं।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले सुनील सिंह

» ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार महंगाई और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में 27 विधानसभा चुनाव की सियासी तैयारियां तेज होने के साथ ही छोटे दल भी अपनी राजनीतिक भूमिका और गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर सक्रिय हो गए हैं। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने नई दिल्ली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के

बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोकदल की भूमिका, सीटों की हिस्सेदारी और विपक्षी गठबंधन में पार्टी की भागीदारी पर चर्चा हुई।

बैठक में पंचायत चुनाव और पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुद्दा भी उठा। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की भावना के अनुरूप पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और प्रभावी भूमिका देने पर चर्चा हुई। लोकदल की राजनीति में किसान और ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे प्रमुख रहे हैं, ऐसे में इन्हें आगामी चुनावी विमर्श से जोड़ने की तैयारी के संकेत भी बैठक से मिले। दोनों नेताओं के बीच किसानों, ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार, महंगाई और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। पिछले दिनों सुनील सिंह हाल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। उस मुलाकात में भी 27 के चुनाव और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई थी।

पंजाब में विस चुनाव से पहले गरमाई सियासत

ड्रग्स से लेकर पानी पर तकरार, विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल, जाखड़ ने पंजाब पुलिस पर उठाया सवाल

» अकाली दल, भाजपा ने कसी कमर, आप व कांग्रेस की भी तैयारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब में विस चुनाव में अभी छह महीने बाकी है। पर वहां पर सियासी माहौल बनने लगा है। विपक्ष सत्ता में बैठी आप सरकार को घेरने का कोई भी मौका नही छोड़ता। जहां अकाली दल व भाजपा सीएम मान पर निशाना साध रहे वहीं आप भी कांग्रेस व अन्य दलों पर पलटवार करने में पीछे नहीं रहती है। अब तो पंजाब नशा से लेकर पानी तक मुद्दों पर वार पलटवार जारी है।

सीएम मान ने राज्य के पानी को किसी को भी न देने की बात कही है तो वहीं संगरूर में आत्महत्या मामले को लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने भगवंत मान सरकार पर हमला किया। कु ल मिलाकर सभर पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कसाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ड्रग्स, पुलिस व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संगरूर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और आम आदमी इतना मजबूर हो चुका है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी उसे राहत नहीं मिलती। बिक्रम मजीठिया ने कहा कि संगरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला है। ऐसे में यहां इस तरह की घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर भगवंत मान की सरकार की विफलता बताया। मजीठिया के मुताबिक, पिछले 14 दिनों में संगरूर में यह तीसरी ऐसी घटना है।

पानी की एक भी बूंद बांटने का सवाल नहीं : मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मेले में उन्होंने पंजाब के पानी के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि पंजाब का फालतू पानी किसी भी दूसरे राज्य को नहीं दिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि पूर्व में सत्ता में रही सरकारों ने पंजाब के पानी का सही तरीके से हिसाब-किताब नहीं रखा, लेकिन अब पानी के हर हिस्से का हिसाब रखा जाएगा। मान ने कहा, पंजाब के पास किसी दूसरे राज्य के साथ बांटने के लिए कोई फालतू पानी नहीं है। एक बूंद भी बांटने का सवाल ही नहीं उठता। पिछली सरकारों ने अपने निजी लाभ के लिए राज्य के हिस्से का नदी का पानी सौंपकर पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचाया। हमारी सरकार ऐसे समझौते दोबारा नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 21 मई से अगले साल 21 मई तक पानी का पूरा हिसाब होता है और इसी हिसाब के आधार पर पानी दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब के पानी को लेकर किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी और जितना पानी नियमों के मुताबिक उपलब्ध होगा, उसी के अनुसार पानी का बंटवारा किया जाएगा। मान से साफ किया कि पंजाब के कीमती जल संसाधनों के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

अकाली नेता ने आरोप लगाया कि संगरूर में कमजोर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है. उन्होंने दावा किया कि जिन अधिकारियों को उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने निलंबित किया था, उन्हें बाद में एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई. हालांकि, ये सभी आरोप मजीठिया के बयान पर आधारित हैं।

पंजाब में पुलिसकर्मियों को एडवाइजरी पर सुनील जाखड़ ने सरकार को घेरा

पंजाब में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। जाखड़ के मुताबिक, पुलिसकर्मियों की हो रही हत्याओं के बीच पंजाब सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें पुलिसकर्मियों को यात्रा के दौरान कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। जाखड़ के मुताबिक, एडवाइजरी में पुलिसकर्मियों से अकेले यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया है। इसके अलावा ड्यूटी के अलावा आने-जाने के दौरान वर्दी पहनकर यात्रा न करने और दोपहिया वाहन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। संभव हो तो पुलिसकर्मियों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, पंजाब किस दिशा में जा रहा है? पंजाब में इन दिनों अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस ही गैंगस्टरों और बदमाशों से डरी हुई नजर आ रही है। जाखड़ ने आगे कहा, अपराधियों द्वारा कई पुलिस अधिकारियों की हत्या किए जाने के बाद, माना जा रहा है कि पंजाब सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जो राज्य की कानून-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। । उन्होंने एडवाइजरी में कही गई बातों का जिक्र करते हुए लिखा, इस एडवाइजरी में पुलिसकर्मियों से कहा गया है कि वे अकेले यात्रा करने से बचें, ड्यूटी के अलावा आने-जाने के दौरान वर्दी पहनकर यात्रा न करें, दोपहिया वाहनों से यात्रा न करें और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। सुनील जाखड़ ने अपनी पोस्ट में पंजाब पुलिस के पुराने दौर का जिक्र करते हुए सवाल किया, सवाल उठता है कि क्या यह वही पंजाब पुलिस है, जिसने कभी राज्य से आतंकवाद का सफाया किया था?। जाखड़ की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमृतसर में ड्यूटी के दौरान एक एएसआई की हत्या के बाद पंजाब में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

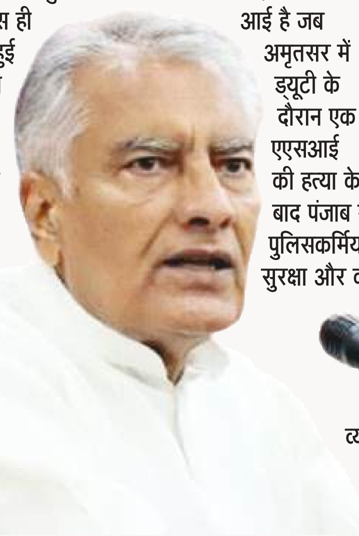

ड्रग्स की डिलीवरी पिज्जा और बर्गर से भी ज्यादा तेजी से हो रही : बिक्रम मजीठिया

मजीठिया ने पंजाब में ड्रग्स की स्थिति को लेकर भी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ड्रग्स की डिलीवरी पिज्जा और बर्गर से भी ज्यादा तेजी से हो रही है। उन्होंने कहा कि संगरूर में पुलिस और राजनीतिक लोगों के बीच गठजोड़ होने के आरोप सामने आ रहे हैं और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

आप के अध्यक्ष अमन अरोड़ा के विस क्षेत्र का मामला

मजीठिया ने कहा कि जिस जगह यह घटना हुई, वह आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के विधानसभा क्षेत्र में आता है उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। मजीठिया ने दावा किया कि एक वीडियो को डिलीट करने के लिए भी दबाव बनाया गया था। उन्होंने फिरोजपुर में एक युवक की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार ने ड्रग्स से मौत की बात कही, लेकिन पुलिस ने इस पर आपत्ति जताई मजीठिया ने अमन अरोड़ा पर वित्तीय धोखाधड़ी और ड्रग्स मामलों से जुड़े होने के भी आरोप लगाए।

कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है : संदीप पाठक

बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है ।संदीप पाठक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि ये कांग्रेस की बढ़ती हताशा और उसके बौद्धिक दिवालियापन को दिखाता है। संदीप पाठक ने एक्स पर लिखा, यह कुछ और नहीं, बल्कि कांग्रेस की बढ़ती हताशा और बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण है। जब आप भारत के मूल्यों से जुड़ाव नहीं रखते तो आप स्वयं भारत से ही अपना जुड़ाव खो देते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की है, जो अपना रास्ता भटक गई है। बीजेपी नेता संदीप पाठक से पहले किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, प्रदीप भंडारी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे बेहद शर्मनाक बताया है।

जिद... सच की

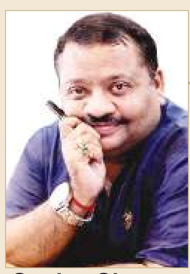

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

केयरिंग करने वालों को अब मिल सकेगा न्याय

> हम उम्मीद कर सकते हैं कि व्यापक नीति बनाते समय सरकार चिल्ड्रेन होम या बाल संरक्षण संस्थानों को यह जिम्मेदारी भी देगी कि वे भोजन और छत के साथ-साथ ऐसी शिक्षा भी दें कि बालिग होने के बाद वे अपनी योग्यता के साथ उच्च शिक्षा या नौकरियों में अपना दावा मजबूती से रख सकें। सिर्फ आरक्षण देने से बात नहीं बनेगी। माता-पिता से वंचित ऐसे बच्चों को योग्य नागरिक बनाना भी सरकार का ही दायित्व होना चाहिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो एक गंभीर सामाजिक समस्या पर अदालत का संवेदनापूर्ण हस्तक्षेप कहा जाएगा। बता दें चल्ड्रेन होम और बाल देख-रेख संस्थानों से 18 साल की उम्र पूरी कर बाहर निकलने वाले युवाओं, जिन्हें केयर लीवर्स कहा जाता है, के लिए शिक्षा व नौकरियों में एक फीसदी आरक्षण और अन्य सहूलियतों के लिए स्थायी नीति बनाने का निर्देश देना राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक कदम है। जब तक स्थायी नीति नहीं बनती तब तक आयु सीमा में छूट, परीक्षा शुल्क से पूर्ण राहत, छात्रवृत्ति और ब्याज-मुक्त ऋण जैसी अंतरिम राहतें देने के आदेश दिए गए हैं। चिल्ड्रेन होम और बाल संरक्षण संस्थानों में ऐसे असहाय बच्चे पलते हैं, जिनका दुनिया में अपना कोई नहीं होता। जिजीविषा उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलने के लिए विवश करती रहती है। अब गेंद केंद्र और राज्य सरकार के पाले में है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस अवसर का उपयोग देश के समक्ष एक आदर्श आफ्टरकेयर मॉडल प्रस्तुत करने के लिए करे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि व्यापक नीति बनाते समय सरकार चिल्ड्रेन होम या बाल संरक्षण संस्थानों को यह जिम्मेदारी भी देगी कि वे भोजन और छत के साथ-साथ ऐसी शिक्षा भी दें कि बालिग होने के बाद वे अपनी योग्यता के साथ उच्च शिक्षा या नौकरियों में अपना दावा मजबूती से रख सकें। सिर्फ आरक्षण देने से बात नहीं बनेगी। माता-पिता से वंचित ऐसे बच्चों को योग्य नागरिक बनाना भी सरकार का ही दायित्व होना चाहिए।अदालत ने बेहद संजीदगी से इस कड़वी सच्चाई को रेखांकित किया और कहा कि है कि सरकार माता-पिता की तरह इन युवाओं की अंगुली तब तक थामे रखे, जब तक वे अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े न हो जाएं। हाईकोर्ट ने केयर लीवर्स के जीवन की हर व्यावहारिक कठिनाई का समाधान खोजने का प्रयास किया है। संस्था छोड़ने से पहले 17.5 साल की उम्र से ही आधार कार्ड, बैंक खाता और पहचान पत्र बनाने के निर्देश देना व्यवस्था की बुनियादी खामी को दूर करता है। अक्सर देखा गया है कि कागजात न होने के कारण ये युवा किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते थे। इसके अलावा, राज्य व जिला स्तर पर केयर लीवर्स सचिवालय और आफ्टरकेयर आइडी कार्ड की व्यवस्था से इनका एक प्रामाणिक डिजिटल डेटाबेस तैयार हो सकेगा, जिससे नीतिगत लाभ सीधे इन तक पहुंचेंगे। उच्च शिक्षा के लिए मासिक छात्रवृत्ति, मुफ्त हॉस्टल सुविधा और पांच लाख रुपए तक का ब्याज-मुक्त ऋण देना इन युवाओं को न केवल आर्थिक संबल प्रदान करेगा, बल्कि उनमें यह आत्मविश्वास भी जगाएगा। हाईकोर्ट ने जिस प्रकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य बाल न्याय परिषद का गठन करने, प्रत्येक जिले में केयर लीवर्स सचिवालय बनाने और आठ सप्ताह में अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जो इस बात का संकेत है कि अदालत केवल फैसला सुनाकर शांत बैठने वाली नहीं है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

चुनावी चंदे के मामले में सियासी दल हों जवाबदेह

अशोक लवासा

बीबीसी की हालिया खोजी खबर में छह पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को मिले भारी-भरकम चंदे के बारे में जांच ने भारतीय राजनीति का जाना-पहचाना लेकिन दिलचस्प पहलू उजागर किया है। ये वह बुराई है जो चंहु ओर व्याप्त है। सियासी दल और उन्हें फायदा देने वाले लोग इस गठजोड़ से फलते-फूलते हैं, भले यह निंदनीय, गैर-कानूनी व परेशानीजनक लगे। इससे पहले, 18 जुलाई, 2025 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की घोषित आय में 223 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट कहती है, उक्त श्रेणी में आते 2764 दलों में से केवल 739 ने ही उस साल के अपने वित्तीय रिकॉर्ड चुनाव आयोग को सौंपे थे, जो कानून अनुसार राजनीतिक पार्टियों के भविष्य व भाग्य का एकमात्र विधाता है।

'चुनाव प्रणाली को साफ-सुथरा बनाना' शीर्षक से एक प्रेस नोट में, चुनाव आयोग ने (9 अगस्त 2025) कहा कि उसने 'चुनाव प्रणाली साफ-सुथरी बनाने की व्यापक और सतत रणनीति के तहत' 2854 पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त सियासी दलों में से 334 को सूची से हटा दिया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिन छह पार्टियों की चर्चा हो रही है, वे चुनाव आयोग की इस 'सतत रणनीति' का हिस्सा हैं या नहीं।

16 अक्तूबर, 1994 को, चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत एक आदेश में, मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने 'देश के करीब सभी सियासी दलों — चाहे वे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियां थीं या पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त दल— में व्याप्त खराब कार्यप्रणाली' पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा- 'मुझे अभी तक एक भी ऐसी पार्टी नहीं मिली जो अपना कामकाज उसके अपने संविधान या नियमों-विनियमों में दिए प्रावधानों मुताबिक चला रही हो'। उस आदेश के जरिए, उन्होंने सभी दलों को अपना कामकाज ठीक करने के लिए 'नोटिस' दिया था और घोषणा की कि चुनाव आयोग 'मूक दर्शक' बनकर नहीं रहेगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के तहत पंजीकरण उपरांत केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में अनुच्छेद 3 (भाग 23वां) कहता है कि पंजीकरण के इच्छुक दल को अपने संविधान में बताना होगा कि वह पंजीकरण के 5 साल के भीतर चुनाव लड़ेगा व अगर कोई दल

'6 साल लगातार चुनाव नहीं लड़े' तो वह 'मान्यता प्राप्त दलों' की सूची से हटा दिया जाएगा।' 'सूची से हटाने' (डीलिस्टिंग) का मतलब पंजीकरण रद्द करना नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसा करने का हक नहीं है। इस तरह, पंजीकृत किंतु अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भले ही 'मान्यता प्राप्त' न भी हों, फिर भी वे धारा 29-बी के तहत चंदा पाने और धारा 29-सी के तहत आयकर छूट के हकदार रहते हैं। 'मान्यता' का मामला 'चुनाव चिन्ह आदेश' के आदेश नं. 6 से तय होता है, जो चिन्ह आवंटित करने के उद्देश्य से 'मान्यता प्राप्त' और 'गैर मान्यता प्राप्त' राजनीतिक दलों' में अंतर करता है व उनके वर्गीकरण के नियम तय करता है। इसलिए, चाहे कोई दल सूची से हटा दिया गया हो या 'अमान्यता प्राप्त' श्रेणी में आता हो, उसे चंदा पाने का हक रहता है। जांच का विषय है कि क्या ऐसे चंदे पर आयकर छूट मिलती रही, क्योंकि सूची से हटाने का मकसद ही उन्हें अयोग्य ठहराना है। 'कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव संस्था' में वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता वेंकटेश नायक की रिपोर्ट के अनुसार, 22 दलों के पास 2024 के आम चुनावों के दौरान कुल 18,742.31 करोड़ रुपये की रकम थी। इसमें चुनाव की घोषणा के समय उनके पास मौजूद फंड और चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव खत्म होने के बीच जुटाया 7,416.31 करोड़ रुपये का चंदा शामिल था। केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपे गए हिसाब-किताब के मुताबिक, चुनाव उपरांत इन दलों के हाथ में 14,848.46 करोड़ रुपये था (नकदी, बैंक खातों और एफडी में रखा पैसा शामिल) जोकि चुनाव संबंधित खर्चों पर 3,861.57 रुपये लगने के बाद बचा था। अध्ययन में पाया गया कि बीते दशक में, राजनीतिक चंदे पर कर छूट के कारण सरकारी खजाने को 11,813 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में निजी दानदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों ने सियासी दलों को चंदा देने में कॉर्पोरेट्स को पीछे छोड़ दिया।

वित्त वर्ष 2022-23 में, व्यक्तिगत दानदाताओं ने 2,275.85 करोड़ रुपये छूट का दावा पेश किया, जो कॉर्पोरेट द्वारा किए 514.4 करोड़ रुपये और फर्मों/एसोसिएशन के 115.71 करोड़ रुपये के दावों से कहीं ज़्यादा था। राजनीतिक दलों को मिला घोषित चंदा 2015-16 में 714 करोड़ रुपये (43 दल) से बढ़कर 2023-24 में 7,203 करोड़ रुपये (27 दल) हो गया। तथापि, कुल चंदा रकम (नौ वर्षों में 28,287 करोड़ ररुपये) में से केवल 41.76 प्रतिशत पर ही कर छूट का दावा किया, जिससे शेष 58 फीसदी बारे सवाल उठते हैं।

असल जिंदगी में दबाव की राजनीति का हश्र

ज्योति मल्होत्रा

पिछले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी और पंजाब से आई दो खबरों ने 'दबाव बनाने' का मतलब निस्संदेह साफ़ कर डाला है- एकदम द मर्चेट ऑफ़ वेनिस के शाइलॉक और एंटोनियो जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ वैसा ही। पहली खबर ट्रंप के वाशिंगटन डीसी से आई 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट-2026' को लेकर है, जिसमें भारत जैसे देशों को रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर सौ प्रतिशत तक अतिरिक्त कर लगाने की धमकी दी गई है। अगर ट्रंप ने खुद शेक्सपीयर पढ़ा होता, तो उन्हें अब तक पता चल गया होता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी अभी-अभी एक बड़ा शिखर सम्मेलन संपन्न करवा कर हटे हैं जिसमें दुनिया के तीन सबसे ताकतवर नेताओं में से दो, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, दोनों ने हिस्सा लिया था। अखबार इस बात से पटे पड़े हैं कि किस तरह पिछले छह महीनों में ईरान के खिलाफ अमेरिका-इस्राइल युद्ध शुरू होने के बाद से, भारत के कुल तेल आयात का 51 फीसदी रूस से आया है। हमारे सेनाध्यक्ष गत सप्ताह ज़्यादातर समय रूस में रहे, नए हथियारों के सौदों पर बातचीत के सिलसिले में।

अगर ट्रंप रूस-ईरान टैरिफ कानून पर साइन कर देते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि इससे मोदी पर किसी किस्म का दबाव बन पाएगा? क्या उन्हें लगता है कि भारत डर के मारे पीछे हट जाएगाङ्कुछ-कुछ रोते-बिलखते और नाक सिकोड़ते हुए एंटोनियो की तरह, इससे पहले कि पोर्शिया आकर शाइलॉक का खेल पलट दे और भारत रूस के साथ अपने बहुपक्षीय रिश्ते खत्म कर देगा? फिर यहां पंजाब में भाजपा है, जो इस सूबे में भी अपना प्रभाव का विस्तार करना चाहती है, जो कि एक तरह से दबाव ही है, इस उम्मीद से कि इस सीमावर्ती राज्य के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में उसे अपना प्यार देकर नवाज़ेंगे। चुनाव में छह महीने बचे हैं, हर राजनीतिक दल का निशाना भी यही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस अपनी बिखरी पड़ी राज्य इकाई को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल जिला-जिला घूम रहे हैं, अपनी पार्टी में फिर से जान फूंकने की कोशिश में, ताकि भविष्य के संभावित साथी, भाजपा के साथ लेन-देन में हाथ ऊपर रखने में मदद मिल पाए।

बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या पंजाब इन दिनों शतरंज खेल रहा है या अपने भविष्य के लिए जुआ खेल रहा है। अगर यह पहला है, तो इस बड़े खेल में मोहरे कौन हैं? अगर दूसरा है, तो पत्ते किसके हाथ में हैं? तो गत सप्ताह जो बात खास रही, वह है जिस ढंग से भाजपा ने पंजाब में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पठानकोट में पगड़ी पहनकर और तलवार लहराते हुए दिखे, और पंजाबी में कुछ शब्द बोलने के साथ पार्टी की नशा-विरोधी यात्रा शुरू की; संयोगवश, नबीन और राज्य इकाई अध्यक्ष केवल ढिल्लों, दोनों ने, लिखा-लिखाया भाषण पढ़कर सुनाया। चुनाव प्रचार शुरू करने के स्थल का चयन— पठानकोट का एकता स्थल, वह यादगार जगह जहां से जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मई 1953 में जम्मू-कश्मीर में लागू तत्कालीन परमिट व्यवस्था को हटाने के वास्ते जम्मू तक की अपनी यात्रा शुरू की थी-भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुखर्जी भाजपा के शीर्ष नेताओं में एक कद्दावर हस्ती थे।

पार्टी इस साल उनकी 125वीं जयंती मना रही है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ उनका दिया नारा 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा' दशकों तक गूंजता रहा। जब 2019 में यह अनुच्छेद हटाया गया,तो भाजपा ने विचारधारा आधारित अपने तीन वादों में से एक को पूरा किया, जो 1980 में पार्टी शुरू होने के बाद से सदा कायम रहे (शेष दो में एक था राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और दूजा है, समान नागरिक संहिता लागू करना—उत्तराखंड यह पहले ही कर चुका है, जबकि गुजरात, असम और मध्य प्रदेश इस राह पर हैं; ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं)। पठानकोट में नबीन का संदेश एकदम साफ था। भाजपा पंजाब को लुभाना चाहती है, लेकिन अपनी विचारधारा की कीमत पर नहीं। सवाल यह है कि आने वाले महीनों में यह कैसे हो पाएगा। भाजपा चुनाव मिलकर लड़ने के वास्ते अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी या नहीं? दोनों पक्षों को बखूबी पता है कि गठबंधन उनके आपसी फायदे के लिए कारगर हो सकता है— यह होने पर जहां भाजपा उम्मीदवार पंजाब के गांवों में घुसने लायक हो सकेंगे, जहां पर ज़्यादातर आबादी सिखों की है, और अब तक उनका स्वागत काले झंडों से होता आया है; तो वहीं अकाली दल की पहुंच शहरी इलाकों में भाजपा के हिंदू मतदाताओं तक बन सकती है।

कम से कम, कागजों पर तो यही गणित है, जब पिछले सप्ताह से पंजाब की लड़ाई शुरू हो रही है। फिर यहां पर अमृतपाल सिंह, खडूर साहिब से कट्टरपंथी सांसद, जो कि पिछले तीन साल से डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, और जिसके राजनीतिक संगठन, 'वारिस पंजाब दे' का वजूद अन्य राजनीतिक दलों के अलावा नजर आ रहा है। समस्या यह है कि असल जिंदगी में, दबाव कभी इस तरह से काम नहीं करता। ट्रंप यह जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी-1980 के दशक में पंजाब और हरियाणा में बतौर एक युवा प्रचारक पाए उनके अनुभवों ने उन्हें इस सीमावर्ती सूबे के लोगों की वह समझ दी है जो भाजपा में बहुत कम लोगों को होगी। मोदी जानते हैं कि भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन कारगर बनाने के लिए केवल जातीय कार्ड चलने से अधिक पासे चलने होंगे (जैसे कि जाट सिख, दलित सिख, पंजाबी खत्री) या धर्म (गुरुद्वारा, मंदिर, डेरा) का जोड़-तोड़; यह कि केवल 13 सांसद और लगभग नगण्य मुस्लिम आबादी वाला यह छोटा सा राज्य अभी भी देश का मूड बदलने में सक्षम है।

पेट का लगातार बढ़ना कई बीमारियों का खतरा

चर्बी कम करने के लिए क्या करें?

पेट की चर्बी को सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करके कम करना संभव नहीं माना जाता। शरीर की कुल अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए संतुलित खान-पान और नियमित शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है। खाने में हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। मीठे पेय और ज्यादा चीनी का सेवन कम करें। बहुत ज्यादा तला-भुना और जंक फूड सीमित करें। रोजाना नियमित शारीरिक गतिविधि या व्यायाम करें। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचें। पर्याप्त और नियमित नींद लें। तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश करें। वजन या कमर लगातार बढ़ रही है तो डॉक्टर से सलाह लें।

हाई ब्लड प्रेशर

पेट का निकलना (यानी पेट की चर्बी या मोटापा) और हाई ब्लड प्रेशर का आपस में बहुत गहरा संबंध है। पेट के आस-पास जमा होने वाली चर्बी धमनियों को सिकोड़ देती है, जिससे दिल पर खून पंप करने का दबाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।

फैटी लिवर

पेट का निकलना (बढ़ना) और लिवर में खराबी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आमतौर पर पेट के बाहर निकलने के दो मुख्य कारण होते हैं:- पहला, फैटी लिवर के कारण पेट के आसपास चर्बी (बेली फैट) का जमा होना। दूसरा, लिवर की बीमारी गंभीर होने पर पेट में पानी भर जाना, जिसे डॉक्टरी भाषा में जलोदर कहते हैं। इसलिए लिवर को ठीक रखने और पेट को अंदर करने के लिए आपको अपनी जीवनशैली और खानपान में तुरंत सुधार करने की आवश्यकता है।

अगर आपके पेट के आसपास लगातार चर्बी बढ़ रही है, तो इसे सिर्फ शरीर की सुंदरता से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज न करें। पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी यानी एब्डॉमिनल फैट शरीर में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है। खास बात यह है कि शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी सिर्फ बाहर से दिखाई देने वाली समस्या नहीं होती, बल्कि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए बढ़ती कमर को केवल वजन बढ़ना मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। समय रहते खान-पान और जीवनशैली में बदलाव करके मोटापे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है। पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना, अधिक मीठे और जंक फूड का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और लंबे समय तक बैठे रहना इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इसके अलावा नींद की कमी, तनाव और कुछ हार्मोनल या आनुवंशिक कारण भी वजन बढ़ने में भूमिका निभा सकते हैं। अगर वजन तेजी से बढ़ रहा है, पेट की चर्बी लगातार बढ़ रही है या इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई ब्लड शुगर, सांस फूलना, अत्यधिक खर्राटे या लगातार थकान जैसी समस्याएं हैं, तो डॉक्टर से जांच कराना बेहतर है।

जोड़ों की समस्या

पेट का निकलना, ज्यादा वजन घुटनों और दूसरे जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, जिससे दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। बढ़ते वजन के कारण शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन (सूजन) होना इसका मुख्य कारण है। मोटापा अक्सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा होता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है? यह यूरिक एसिड जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर गठिया का कारण बनता है।

टाइप-2 डायबिटीज

पेट का निकलना (यानी पेट के आसपास चर्बी या विसरल फैट का बढ़ना) टाइप-2 डायबिटीज होने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण माना जाता है। जब पेट पर अतिरिक्त चर्बी जमा होती है, तो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के प्रति सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके कारण रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और व्यक्ति टाइप-2 डायबिटीज का शिकार हो जाता है।

कोलेस्ट्रॉल की समस्या

पेट का निकलना और हाई कोलेस्ट्रॉल का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब पेट की चर्बी बढ़ती है, तो यह सीधे आपके लिवर के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। लिवर खराब कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन बढ़ा देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है।

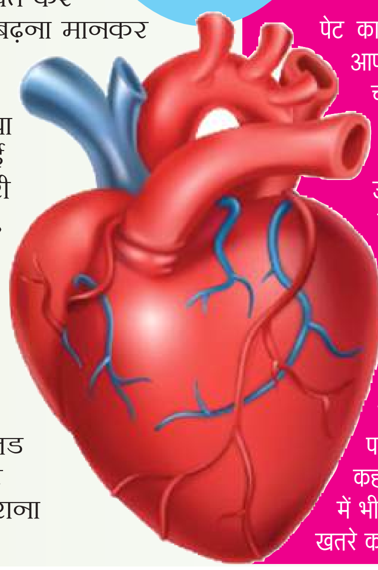

हृदय रोग

पेट का बाहर निकलना और हृदय रोग के बीच सीधा और गहरा संबंध है। पेट पर जमा होने वाली चर्बी को विसरल फैट कहा जाता है, जो सामान्य वजन वाले लोगों में भी हृदय रोग, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देती है।

हंसना मना है

वाईफ: जानू हम ना.. मंडे .. शॉपिंग, ट्यूसडे .. होटल, वेडनेसडे .. आउटिंग, थर्सडे .. डिनर, फ्राइडे .. मूवी, सैटरडे .. पिकनिक जायेंगे। जानू कितना मजा आएगा ना।
हसबंड: यस, और संडे मंदिर.. वाइफ: क्यों..? हसबैंड: भीख मांगने।

अमीर आदमी: आज मेरे पास 14 कार, 18 बाइक्स, 4 बंगले, 3 फार्महाउस है, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी: मेरे पास बेटा है, जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है।

डॉक्टर- तुम्हारी नब्ज तो ठीक चल रही है, बिल्कुल घड़ी की तरह, लड़की- अरे नहीं, आपने गलती से नब्ज की जगह मेरी घड़ी पर हाथ रख दिया है।

प्यार को मत छुपाओ उसे जरुरत है जताने की, अपनी प्रतिभाओं को मत छुपाओ उन्हें जरुरत है बढ़ाने की, अब और परफ्यूम मत लगाओ तुम्हें जरुरत है नहाने की।

तु चांद मांगो मैं चांद दे दूं, तु रात मांगो मैं रात दे दूं, तु दिल मांगो मैं दिल दे दूं, तु प्यार मांगो... क्या यार, भीक मांगने की भी एक लिमिट होती है।

तुम क्या जानों गम क्या होता है? तुम क्या जानो गम किसे कहते है? तुम क्या जानो गम क्या चीज होती है? तुमने तो हमेशा फेवीकोल यूज किया है!

कहानी — गौरैया और बंदर

एक जंगल के घने पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन बीता रहे थे। फिर सर्दियों के मौसम में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे। वो सोच रहे थे काश कहीं से आग सेंकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। और पत्तियों को जलाने का उपाय करने लगे। ये सब पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। वो बंदरों से बोल पड़ी, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ-पैर भी हैं, तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग-अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। यह सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोल पड़ी, यह जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग दो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इतने में फिर से गौरैया बोल उठी, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक गुस्साए हुए बंदर से रहा न गया और उसने पेड़ पर चढ़कर गौरैया के घोसले को तोड़ दिया। यह देख चिड़िया दुखी हो गई और डर कर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

कार्यक्षेत्र में दोपहर बाद नए अवसर और लाभ मिलने के योग बनेंगे। व्यापारिक योजनाओं में दोपहर के बाद तेजी आएगी, बड़ा लाभ संभव है। रुका धन वापस आएगा।

वृषभ

करियर और दफ्तर के काम में तेजी देखने को मिलेगी। कारोबारियों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नए सौदों में लाभ होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत बढ़ेगी।

मिथुन
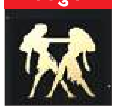
नौकरी में हैं तो इस दिन स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी, राहत महसूस होगी। कारोबारी हैं तो भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंगे।

कर्क

दोपहर के बाद अष्टम चंद्र का प्रभाव शुरू होने से सतर्क रहने की जरूरत है। दफ्तर की गॉसिप से दूर रहें, विरोधी हावी हो सकते हैं। अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।

सिंह
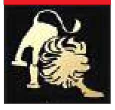
व्यापारिक मामलों में साझेदारी से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। नौकरी-पेशा जातकों को टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कन्या

दोपहर बाद कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी, विरोधी परास्त होंगे। कारोबारी हैं तो पुराने रुके हुए काम निपटाने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला

नौकरी-पेशा हैं तो मन थोड़ा चंचल या दुविधा में रह सकता है। व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें, अनुभवी लोगों की सलाह लें। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

वृश्चिक

नौकरी-पेशा हैं तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। कारोबारी हैं तो बहस से बचें, शांति से काम निपटाएं। घरेलू मामलों में जीवनसाथी की राय जरूर लें।

धनु
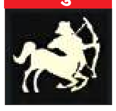
नौकरी-पेशा के पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, छोटी यात्राएं फलदायी रहेंगी। भाई-बहनों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

मकर

नौकरी-पेशा हैं तो वितीय मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता रखें। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, अपनों का साथ मिलेगा।

कुम्भ
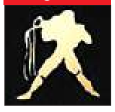
नौकरी-पेशा हैं तो उत्साह और ऊर्जा बढ़ेगी। कारोबारी हैं तो आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, नए विचार आएंगे। लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी, आकर्षण बना रहेगा।

मीन

दफ्तर में अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों के विवाद में न पड़ें। कारोबारी हैं तो फिजूलखर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, बजट संभालें। नींद पूरी लें और ध्यान करें।

बिहार में छात्रा से बदसलूकी पर भड़कीं खुशबू पाटनी

बिहार के जमुई जिले से सामने आई एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है! एक नाबालिग छात्र और छात्रा के साथ सरेआम गुंडागर्दी, बेरहमी से मारपीट और छात्रा से छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस घटना पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का बेहद तीखा और बेबाक रिएक्शन सामने आया है। खुशबू ने वीडियो जारी कर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और समाज की बीमार मानसिकता पर सीधे तीखे सवाल दागे हैं। बिहार के जमुई में गमछा लपेटे एक शख्स द्वारा स्कूटी सवार लड़के-लड़की को घेरकर मारना, लड़की को हैरास करना और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, खुशबू पाटनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भड़ास निकालते हुए कहा, महान भारतज विश्वगुरु बनेगा भारत, ऐसा बनेगा? जहां औरत जात की कोई इज्जत ही नहीं है? खुशबू ने आरोपियों की क्लास लगाते हुए कहा कि ये वही अनपढ़-जाहिल हैं जो अपनी दिहाड़ी नहीं कमा पाते और नशे में धुत रहते हैं। इन्हें अपनी लाइफ का मकसद ही नहीं पता और ये दूसरों के हाथ के कीड़े बने हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी की मर्जी से साथ घूमने या दोस्ती से इन अनपढ़ों को इतनी चिढ़ क्यों होती है? आरोपियों की मानसिकता की धज्जियां उड़ाते हुए खुशबू ने कहा कि ऐसे लोगों को कोई देखता भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा, बचपन से इसने अपनी मां को पिटते हुए देखा होगा, बहन के साथ गलत होते देखा होगा, इसलिए इसको यह सब नॉर्मल लगता है। बिहार वालों, इस बार इस घटना को अपनी ईगो पर ले लो। क्या हम सिर्फ सरकार को ब्लेम करते रहेंगे? पीपल मेक द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट मेक्स द पीपल, तो क्या हम अपने अंदर झांककर नहीं देखेंगे? वीडियो के अंत में उन्होंने संविधान और अपनी आजादी की बात करते हुए कहा कि गमछा वाले और उसके पूरे 'छपरी लॉट' को ऐसी भयानक सजा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह कांप उठे। उन्होंने साफ कहा, मेरा संविधान मुझे हक देता है कि मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, तुझसे पूछके जिंदगी नहीं काटूंगी मेरे भाई!

बोलीं - लॉ एंड ऑर्डर क्यों हिला हुआ है

'राका' के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 37 लोगों ने रचा इतिहास

आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन अभिनीत, वी. अरुणकुमार (एटली) द्वारा निर्देशित और सन पिक्चर्स के कलानिधि मारन की बनाई बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' ने सिनेमाई तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फिल्म ने रियल-टाइम में मोशन-कैप्चर किए गए सर्वाधिक लोगों का रिकॉर्ड श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह रिकॉर्ड एक ही समय में 37 कलाकारों के रियल-टाइम मोशन कैप्चर के जरिए बनाया गया, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि मानी जा रही है। यह रिकॉर्ड फरवरी 2026 में बनाया गया था और 15 सितंबर 2026 को इसे आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सीनियर एडजुडिकेटर स्वप्निल डांगरिकर ने एक विशेष समारोह में अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली को आधिकारिक प्रमाणपत्र सौंपा। इस अवसर पर फिल्म की मुख्य कास्ट और क्रू भी मौजूद रही। इस उपलब्धि पर अल्लू अर्जुन ने कहा, हम इस असाधारण उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। यह सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर एक नया मानदंड स्थापित करने वाला क्षण है। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रयासों को मान्यता दी। यह उपलब्धि मेरे निर्देशक एटली के विजन, पूरी टीम की मेहनत और सन पिक्चर्स के अटूट समर्थन के बिना संभव नहीं थी।

अल्लू अर्जुन बोले- हम इस उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं

370 रुपये की बिरयानी विवाद

प्रणित मोरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

बिग बॉस 19 फेम स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और उनका 370 रुपये की बिरयानी वाला विवाद फिर से सुर्खियों में हैं। कुछ महीने पहले गुरुग्राम में उनके स्टैंड-अप शो के दौरान एक दर्शक हिमांशु जांगड़ा ने डेट और 370 रुपये की बिरयानी से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा। 35 साल के प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा, दोनों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां प्रणित ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। यही नहीं, प्रणित ने फिर से अदालत में सफाई दी है। प्रणित ने लगे हाथ अदालत में सफाई भी दी है। कहा कि विवादित वीडियो उनकी पीआर टीम ने बिना सहमति के अपलोड की थी। 370 रुपये की बिरयानी का यह पूरा विवाद प्रणित मोरे के गुरुग्राम शो में हुआ था, जहां क्राउड वर्क के दौरान एक दर्शक की बेहूदा टिप्पणी खूब वायरल हो गई। कोर्ट में प्रणित मोरे की ओर से आगे कहा गया, एफआईआर दर्ज होने से पहले ही जैसे ही मुझे स्थिति की गंभीरता का पता चला मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। उस समय मैं यात्रा कर रहा था, और मेरी टीम ने वीडियो पब्लिश करने से पहले मेरी मंजूरी नहीं ली थी। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रणित मामले में ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं और उनकी मांग सिर्फ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की है। गुरुग्राम के स्टैंड-अप शो में क्राउडवर्क के दौरान यह पूरा विवाद शुरू हुआ। दर्शक हिमांशु जांगड़ा ने इसमें अपनी एक डेट का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने एक महिला के लिए चिकन बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए थे। वह इसके बदले महिला से सेक्सुअल फेवर की इच्छा रख रहे थे। इस बयान पर विवाद हुआ और महिलाओं के प्रति ऐसी घटिया सोच पर सवाल उठे।

कॉमेडियन की सफाई- टीम ने बिना पूछे डाला वीडियो

रानी मुखर्जी की मां का निधन

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। यश राज फिल्म्स ने मंगलवार, 22 सितंबर को एक बयान में इस खबर की पुष्टि की। परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया है। उनकी मौत की वजह अभी तक नहीं बताई गई है। यश राज फिल्म्स ने अपने बयान में कहा, भारी मन से हम यह जानकारी दे रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां, 75 वर्षीय श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर में निधन हो गया। परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए बहुत आभारी है। इस गहरे दुख के समय में प्राइवेसी बनाए रखने का सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है। कृष्णा मुखर्जी को कई वर्षों तक कई पब्लिक इवेंट्स में अभिनेत्री के साथ देखा गया था। कृष्णा मुखर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी थीं और उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था। रानी अक्सर अपनी मां के साथ अपने गहरे रिश्ते के बारे में बात करती रही हैं। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी की परफॉर्मेंस के लिए कृष्णा एक बड़ी प्रेरणा थीं। इस फिल्म में अभिनेत्री ने एक ऐसी बंगाली मां का किरदार निभाया था, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए लड़ती है। 2023 में फिल्म के प्रमोशन इवेंट में बात करते हुए, रानी ने बताया कि हालांकि उन्होंने असल जिंदगी की कहानी से जुड़े संदर्भों का अध्ययन किया था लेकिन उनके किरदार का ज्यादातर हिस्सा उनकी अपनी मां से प्रेरित था। आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा यश राज फिल्म्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वह रानी मुखर्जी के पति भी हैं। रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल 2014 को मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक आदित्य चोपड़ा से शादी की थी। यह शादी इटली में एक निजी समारोह में हुई थी।

75 की उम्र में कृष्णा मुखर्जी ने ली आखिरी सांस

अनंत नाग दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित

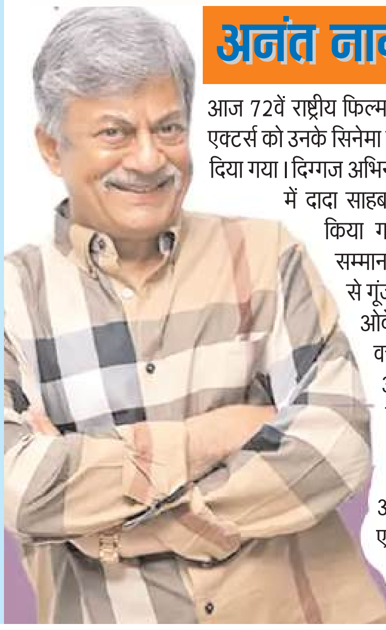

आज 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन हुआ, जिसमें एक्टर्स को उनके सिनेमा जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवॉर्ड लेते समय उन्हें सम्मान देने के लिए पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और मम्मूटी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। अवॉर्ड लेते वक्त एक्टर काफी भावुक नजर आए। कार्यक्रम के दौरान आनंत नाग के फिल्मी दौर पर केंद्रित करते हुए एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मम्मूटी को चौथी बार बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला। इस दौरान वहां मौजूद सभी कलाकारों ने तालियों से मम्मूटी का सम्मान किया। इस बार कार्तिक आर्यन को भी फिल्म चंदू चैंपियन में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला। कार्तिक के माता-पिता भावुक नजर आए, जब एक्टर अवॉर्ड लेने पहुंचे। वहीं आदित्य धर की फिल्म आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड दिया गया। इसी फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए यामी गौतम ने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता। सम्मान समारोह में श्रीकांत को रजत कमल पुरस्कार प्रदान किया गया। तमिल अभिनेता धनुष को फिल्म कैप्टन मिलर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड- स्पेशल मेंशन (फीचर फिल्म) से सम्मानित किया गया। फिल्म का निर्देशन अरुण माथेश्वरन ने किया है। मनोज मुंतशिर ने 'मैदान' के गाने 'जाने दो' के लिए बेस्ट लिरिक्स का नेशनल अवॉर्ड जीता है। वहीं रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला।

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स

यूसीसी को लेकर फिर कांग्रेस का भाजपा पर प्रहार

समान नागरिक संहिता कोई कानूनी सुधार नहीं समाज में ध्रुवीकरण का हथियार है: जयराम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। यूसीसी को लेकर फिर भाजपा व कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कोई कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि ''विभाजन, व्यवधान और ध्यान भटकाने का एक हथियार'' तथा समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने का एक साधन है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित राज्य सरकार की समिति से बंबई उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के इस्तीफे और समिति के कामकाज को लेकर उठाए गए सवालों का हवाला देते हुए कहा कि इससे कई ''बड़े सवाल'' खड़े होते हैं। उन्होंने एक बयान में सवाल किया कि क्या संविधान सभा ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना की थी, जिसमें हर राज्य अपनी अलग समान नागरिक संहिता बनाए? रमेश ने कहा, ''इसका जवाब है: बिल्कुल नहीं।''

कांग्रेस नेता ने कहा, ''क्या बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना की थी, जिसमें एक राजनीतिक दल की राजनीतिक चालों और हिसाब-किताब के मुताबिक अलग-अलग समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य एक-दूसरे से होड़ करें। इसका जवाब है: बिल्कुल नहीं।'' रमेश ने इस बात का उल्लेख किया कि 17

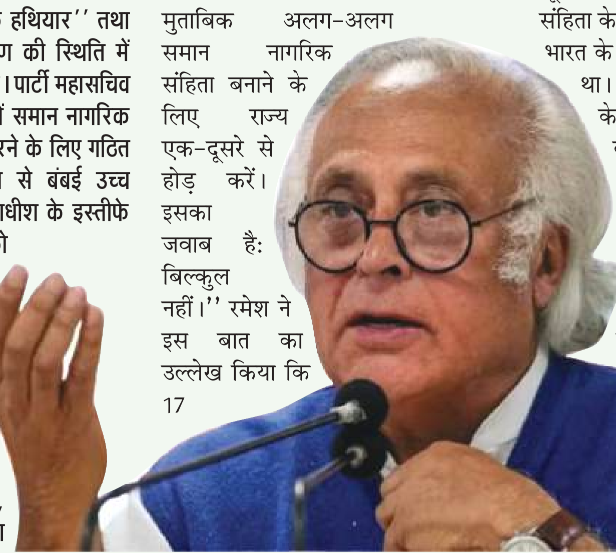

विधि आयोग के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर रही सरकार

उन्होंने कहा कि परामर्श पत्र के पृष्ठ सात के अनुच्छेद 1.15 में आयोग का निष्कर्ष स्पष्ट था कि ''इस स्तर पर समान नागरिक संहिता बनाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।'' रमेश ने कहा कि इसके बजाय विधि आयोग ने भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए अलग-अलग पारिवारिक कानूनों में मौजूद भेदभाव को दूर करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उसी विधि आयोग के निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया, जिसे उसने इस मुद्दे की जांच का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने अपनी-अपनी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

जून16 को मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को विस्तृत अध्ययन के लिए भारत के 21वें विधि आयोग के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि व्यापक अध्ययन के बाद आयोग ने 31 अगस्त 18 को 'पारिवारिक कानून में सुधार' पर अपना परामर्श पत्र जारी किया था। रमेश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि 29 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बाकी दलों की आवाज दबा दी गई है और भाजपा उन्हें ''चुप करा रही है।

राज्य स्तर पर बनायी जा रही ये समान नागरिक संहिता एक जैसे नहीं

रमेश के मुताबिक, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 25 से लागू हुई, जबकि गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 26, असम विधानसभा ने 27 मई 26 और मध्यप्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई 26 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि राज्य स्तर पर बनायी जा रही ये समान नागरिक संहिता एक जैसे नहीं हैं और इनमें ''अलग-अलग प्रावधान, अलग-अलग दंड, अलग-अलग प्रक्रियाएं और कई महत्वपूर्ण छूट'' हैं। उन्होंने उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह ''कई पितृसत्तात्मक परंपराओं को अब भी जारी रखता है'' और राज्य में कानून का पालन करने वाले निवासियों के लिए भी ''कई तरह की समस्याएं'' पैदा कर रहा है।

स्टालिन ने हाईकोर्ट में आधव अर्जुन के मानहानि केस को नकारा

» डीएमके नेता बोले- पार्टी सदस्यों की किसी भी व्यक्तिगत हरकत के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) प्रमुख एमके स्टालिन ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि तमिलनाडु के लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन की ओर से उन पर लगाया गया मानहानि का आरोप बेबुनियाद है। स्टालिन ने कहा कि पार्टी सदस्यों की किसी भी व्यक्तिगत हरकत के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अर्जुन की ओर से दायर मुकदमा खारिज करने और मंत्री पर भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। स्टालिन ने ये दलीलें अर्जुन की ओर से उनके और द्रमुक की आईटी शाखा के खिलाफ दायर एक करोड़ रुपये के मानहानि मामले में दाखिल जवाबी हलफनामे में दीं।

अर्जुन का मुकदमा द्रमुक की आईटी शाखा के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया था कि मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामले का एक आरोपी (जॉन ब्रिटो) अर्जुन का रिश्तेदार है। न्यायमूर्ति के गोविंदराजन थिलकावडी के समक्ष सुनवाई के दौरान स्टालिन ने उनके खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में अंतरिम राहत देने के अनुरोध वाली याचिका का विरोध किया। न्यायमूर्ति थिलकावडी ने मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। द्रमुक प्रमुख ने खास तौर पर इस आरोप से इनकार किया कि कथित पोस्ट उनकी किसी योजना, निर्देश, आदेश या मंजूरी के तहत प्रसारित की गई थी। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने द्रमुक की आईटी शाखा को कोई ऐसा पोस्ट प्रसारित करने का निर्देश या मंजूरी नहीं दी, जिसमें आवेदक (आधव अर्जुन) या उसके परिवार के किसी सदस्य को जॉन ब्रिटो या मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित किसी मामले से जोड़ा गया हो। स्टालिन ने कहा कि असल बात यह है कि जॉन ब्रिटो मीडिया के सामने आया था और दावा किया था कि वह विधायक लीमारोज का भाई है, जो और कोई नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता (आधव अर्जुन) की सास हैं।

हाथियों की संख्या में गिरावट सरकार के लिए चेतावनी : चिदंबरम

» कांग्रेस नेता बोले - हमें शिकार से बचाना होगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भारत में हाथियों की आबादी में आई कमी पर चिंता जताई और इसे सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी (वेक-अप कॉल) बताया। एक्स पर चिदंबरम ने कहा 9 साल में 18 प्रतिशत कम हाथी सरकार के लिए एक चेतावनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक सर्वे का जिक्र था। इस सर्वे में 17 की तुलना में हाथियों की संख्या में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी।

राज्यसभा सांसद ने वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पिछले साल किए गए एक सर्वे में 22,446 हाथियों की गिनती की गई, जो 17 की तुलना में 18 प्रतिशत कम है। हाथियों के प्रति सांस्कृतिक सम्मान और वन्यजीव अपराधों के खतरे के बीच अंतर को उजागर करते हुए चिदंबरम ने कहा, हम गणेश पूजा मनाते हैं। यह सराहनीय है। लेकिन हम हाथियों का शिकार भी करते हैं। इस बीच, विश्व गैंडा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रोजेक्ट राइनो शुरू किया गया है। इसका मकसद एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा, उनके आवास के प्रबंधन और संरक्षण के लिए संबंधित राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना है।

यूडीएफ सरकार कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही : वी. गोविंदम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोच्चि। माकपा ने बारिश प्रभावित मलप्पुरम के दौरे के लिए केरलम के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन द्वारा विशेष विमान का इस्तेमाल और मंत्रियों की कथित प्रायोजित विदेश यात्राओं को लेकर राज्य सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया। इसके साथ ही पार्टी ने कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार पर ''कॉरपोरेट और पूंजीपतियों'' के हित में काम करने का आरोप लगाया। माकपा के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदम ने आरोप लगाया कि इस तरह की यात्राएं ''पद की शपथ का उल्लंघन'' हैं, वहीं पार्टी केंद्रीय समिति के सदस्य पी. राजीव ने आरोप लगाया कि सतीशन मलप्पुरम दौरे के लिए इस्तेमाल किए गए विशेष विमान का खर्च उठाने वाले प्रायोजक का ब्योरा छिपा रहे हैं।

राजीव ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कई सवाल हैं। वह यह बताने से बच रहे हैं कि विशेष विमान का खर्च किसने उठाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले सतीशन ने मंगलुरु की जो यात्रा की थी, उसके प्रायोजक का नाम अब तक सामने नहीं आया है। राजीव

» सीपीएम ने सीएम वी. डी. सतीशन के विशेष विमान और मंत्रियों की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए

ने हाल में मंत्रियों रमेश चेन्निथला (गृह) और ओ. जे. जनीश (खेल) की विदेश यात्राओं को लेकर कहा कि जब जनता बिजली की किल्लत से जूझ रही है, तब केरलम के सत्ताधारी ऐसे पेश आ रहे हैं मानो उन्हें जनता की तकलीफों की कोई परवाह ही न हो। उन्होंने उनकी तुलना सम्राट नीरो से की, जिसके बारे में कहा जाता है कि रोम में आग लगी थी और वह बांसुरी बजा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया, यह सरकार एक प्रायोजित कार्यक्रम की तरह काम कर रही है।

टी20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने टॉप-4 में बनाई जगह

» गेंदबाजी में भारतीयों का दबदबा बरकरार, श्री चरणी और दीप्ति शर्मा पहले और दूसरे स्थान पर काबिज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

आइची नागोया। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन का भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी फायदा मिला है। शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाकर टॉप-4 में जगह बना ली है। वहीं, गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। शेफाली एशियन गेम्स में शानदार फॉर्म में नजर आई थीं। इस प्रदर्शन के बाद वह बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है।

श्री चरणी 799 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। दीप्ति शर्मा दूसरे नंबर पर हैं क्रांति गौड़ ने 15 स्थान की छलांग लगाकर 57वां स्थान हासिल किया है, जबकि नंदनी शर्मा 22 स्थान ऊपर चढ़कर 72वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं पाकिस्तान की कई खिलाड़ियों ने भी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। शवल जुल्फिकार 29वें नंबर पर पहुंच गईं। आयशा जफर 40वें नंबर पर पहुंच गई हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में भी आयशा ने नौ स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 30वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान की सादिया इकबाल आठवें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, कप्तान फातिमा सना ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 24वां स्थान हासिल किया है। बांग्लादेश की संजीदा अख्तर मेघला भी पांच स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 49वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी मियाने स्मिट ने संयुक्त रूप से 53वें नंबर पर पहुंच गई हैं। एनी बॉश टॉप-50 में जगह बनाई। वहीं, एनेरी डर्कसेन ने ऑलराउंडर रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 179 रेटिंग हासिल करते हुए 22वां स्थान प्राप्त किया।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। व्हाइट-बॉल कप्तान मिचेल सैंटनर टीम की अगुआई करेंगे। सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्तूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। चोट के कारण विश्व कप से बाहर रहे माइकल ब्रेसवेल और तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाजी आक्रमण में उनके अलावा लोकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जेमीसन और जैकब डफी जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं। जाक फाउल्क्स और नाथन स्मिथ युवा तेज गेंदबाजों के रूप में टीम का हिस्सा हैं। ऑलराउंडर रचिन रवींद्र दाएं कंधे के खिसकने के कारण टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले फिन एलन और टिम सीफर्ट एक बार फिर न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। तेज गेंदबाज बेन सियर्स को टखने की चोट से उबरने के कारण चयन के लिए विचार नहीं किया गया है।

चुनाव आयुक्तों की अनदेखी की रिपोर्ट आने के बाद देश भर में सियासी बवंडर

विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त का मांगा इस्तीफा

» कांग्रेस, सपा, आप, शिवसेना यूबीटी समेत सभी दलों ने भाजपा को घेरा

» दोनों चुनाव आयुक्त बोले- हमारी नहीं सुनी जाती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एक अंग्रेजी अखबार में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों ने फैसले लेने में मनमानी करने और उनकी आपत्तियों की अनदेखी करने का आरोप लगाने की खबर आने के बाद पूरे देश में सियासी बवंडर मच गया। पूरे विपक्ष ने चुनावव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर करारा प्रहार किया है। बता दें इस रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा देश भर में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा–एसआईआर अभियान के बीच नया विवाद सामने आया है। खुलासा हुआ है कि चुनाव आयुक्त डॉ। सुखबीर सिंह संधू और डॉ। विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार अपनी आपत्तियां चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समक्ष दर्ज कराई थीं। दोनों ने नए वोटरों को जोड़ने और नाम डिलीट करने के मामले में उन्हें अंधेरे में रखने का सवाल भी उठाया था।

इस खुलासे पर कांग्रेस, शिवसेना, सपा, आप समेत कई दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है। एसआईआर की प्रक्रिया जून 25 से बिहार से शुरू हुई थी और अब सभी तीनों चुनाव आयुक्तों की अगुवाई में देश भर में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा चल रही है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, संधू और जोशी ने औपचारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई। दस महीनों में 14 बार आपत्तियां दर्ज कराईं, इसमें एक बार तो एक दिन में ही चार बार सवाल उठाया गया। चुनाव आयुक्तों का कहना है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं और आदेश दिए जा रहे हैं, उसमें उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसी में फैसले लेने का अधिकार तीन अधिकारियों के पास है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। चुनाव आयोग के फैसलों में मतभेदों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं सीईसी ने इन सभी आरोपों का जवाब देते हुए बताया कि मतभेदों के बाद भी फैसला तब लिया जाता है, जब चुनाव आयुक्तों के बीच सर्वसम्मति होती है।

फिर खुली सीईसी की कलई

क्या कोई अदृश्य ताकत ईसी को चला रही : मनीष

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि अगर रिपोर्ट में बताई गई बातें सही हैं तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को कोई अदृश्य ताकत चला रही हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया और ऐसे फैसले लिए गए जो सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं थे, तो चुनाव आयोग के सभी फैसले मनमाने और बिना किसी ठोस आधार के माने जाएंगे, भले ही वे पूरी तरह से गैर-कानूनी न हों। शायद यह मामला महाभियोग की कार्यवाही पर गंभीरता से विचार करने लायक है, लेकिन इससे भी जरूरी बुनियादी सवाल यह है कि चुनाव आयोग की साख को आखिर कैसे बहाल किया जाएगा। बता दें दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मतदाता सूची में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन, वोटर्स के नाम डिलीट करने और उनके नाम दोबारा जुड़ने से संबंधित हैं. एसआईआर के दौरान वोटरों के नाम बहाल करने, अपील फाइल करने के साथ पूरी मतदाता सूची की सुरक्षा से जुड़े मामले भी इसमें हैं. इन सारी आपत्तियों की प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थी. एक लिखित आपत्ति में संधू ने शिकायत दर्ज कराई कि चुनाव आयोग ने दो आयुक्तों की लिखित सलाह के बाहर जाकर काम किया और उनकी कार्यवाही को अनधिकृत और गैरकानूनी करार दिया था।

भाजपा संगठन की तरह काम कर रहा है आयोग : दिग्विजय

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग-एसआईआर विवाद पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि जब से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तब से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन की तरह काम कर रहा है. यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले।

कोई अकेला व्यक्ति चुनाव आयोग नहीं चला सकता : केजरीवाल

चुनाव आयोग को लेकर खुलासे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई अकेला व्यक्ति चुनाव आयोग नहीं चला सकता है। दिल्ली, हरियाणा के चुनाव कैंसिल किए जाएं। चुनाव आयोग के विवाद पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर एक धोखाधड़ी वाली प्रक्रिया है जिसे भाजपा के कहने पर ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं। अब यह बात सच साबित हो गई है. ज्ञानेश कुमार ने जान-बूझकर वोट हटाने का अपराध किया है। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए. जहां-जहां भी ये धोखाधड़ी हुई है, उन सभी चुनावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

तंत्र और यंत्र से चुनाव हराया गया : तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 27 जून 25 को बिहार चुनाव से चंद दिन पहले एकपक्षीय दोषपूर्ण एसआईआर शुरू करने पर हमने सबसे पहले देश को आगाह किया था। 15 से अधिक बार सबूतों के साथ एसआईआर प्रक्रिया पर परजेंटशन देकर जनता और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा था वोट चोरी को उजागर करने के लिए सबसे पहे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। आरजेडी नेता ने कहा कि तीन चुनाव आयुक्तों में से दो आयुक्तों ने 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयोग के निर्णयों व नीतियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, यहां तक की एक दिन में 4 बार आपत्तियां दर्ज करा इनके निर्णयों को अनधिकृत और अवैध बताया लेकिन बहुमत को दरकिनार करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जबरन मनमानी की ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे। बिना किसी का नाम लिए लिखा, दो शीर्ष लोगों के अनैतिक, अवैधानिक कुकृत्यों एवं निर्देशों की पालना कर लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर आमादा ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया गया है उन्हें बचा लिया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने चुनाव आयोग को फर्जीवाड़े का अड्डा बताया है। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह की ओर से यह बयान इंडियन एक्सप्रेस की एसआईआर को लेकर जारी एक रिपोर्ट के बाद आया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग अधिकार को छीन रहा है। कुमार सौरभ सिंह ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा का अड्डा बन गया है। सवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों के इशारे पर भारत के लोकत को पूरी तरह से कुचलने का कार्य किया जा रहा है।

चुनाव आयोग बना फर्जीवाड़े का अड्डा : पीके

चुनाव आयुक्त को जेल जाना होगा : संजय राउत

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे! उन्हें जाना ही होगा! उनके आका देश छोड़कर भाग जाएंगे! चुनाव आयोग से जुड़े खुलासे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. प्रमोद तिवारी की मांग है कि दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच के पत्राचार को सार्वजनिक किया जाए. प्रमोद तिवारी का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी से मिले हुए हैं. संसद में ये मुद्दा उठाया जाएगा, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। वहीं इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टीके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। अखिलेश ने ट्वीट किया, अगर किसी स्वतंत्र संस्था के सदस्यों को निष्पक्ष रूप से काम करने की आज़ादी नहीं है या उनकी चिंताओं को नहीं सुना जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक और चिंताजनक स्थिति है।

शर्मनाक! ओड़िशा में बिहार के जमुई जैसी हुई बर्बरता

» सड़क पर जा रहे जोड़े को ग्रामीणों ने घेरा, युवती की मिन्नतों के बाद भी बदसलूकी व मारपीट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कटक। घटना 18 सितंबर को ढेंकनाल और कपिलाश को जोड़ने वाली सड़क पर हुई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना बिहार के जमुई में हुई ऐसी ही एक घटना के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जहाँ एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जिससे काफी आक्रोश फैल गया था। ओडिशा के ढेंकनाल से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक और युवती को मुख्य सड़क पर रोककर ग्रामीणों के एक समूह ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। यह घटना 18 सितंबर को ढेंकनाल और कपिलाश को जोड़ने वाली सड़क पर हुई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

यह घटना बिहार के जमुई में हुई ऐसी ही एक घटना के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जहां एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जिससे काफी आक्रोश फैल गया था।जानकारी के अनुसार, युवक और युवती मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें सड़क पर रोक लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लोगों का एक समूह जोड़े को घेरे हुए और उनके साथ मारपीट व बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में महिला को उन लोगों से बार–बार विनती करते हुए सुना जा सकता है कि वे उसे छोड़ दें और जाने दें।

फेसबुक और एक्स पर एंटी नेशनल कंटेंट हटाने की मांग खारिज

» सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसमें केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट और मीम्स की पहचान करने, उन्हें हटाने और ब्लॉक करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्हें याचिकाकर्ता ने देश–विरोधी नारे और भाषण बताया था। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने अहमदाबाद के रहने वाले याचिकाकर्ता हितेंद्र कुमार परसोत्तमभाई गाधिया की ओर से पेश वकील बरुण सिन्हा की दलीलों को नहीं माना।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दूसरे विकल्पों पर विचार करने को कहा। सुनवाई के दौरान, बेंच ने इस याचिका को सोशल मीडिया कंटेंट से जुड़े किसी दूसरे लंबित मामले के साथ जोड़ने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट में दी गई दलीलों के मुताबिक, चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता से कहा आप दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। याचिका में केंद्र और कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उन पोस्ट के खिलाफ़ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनके बारे में याचिकाकर्ता का आरोप था कि वे सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और न्यायिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं।

याचिका में सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने की की गई मांग

याचिकाकर्ता ने रिट ऑफ़ मैंडमस (अदालत का आदेश) की मांग की, जिसमें प्रतिवादियों को पब्लिश सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने या हटाने का निर्देश देने को कहा गया। याचिका के अनुसार, जिन पोस्ट को हटाने की मांग की गई, वे ऐसी थीं जिनसे जनता को सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता और न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ भड़काने और सवैधानिक अधिकारियों के अधिकार को कमजोर करने की आशंका थी।याचिका में ऐसे कंटेंट और मीम्स का भी ज़िक्र किया गया, जिनके बारे में याचिकाकर्ता का आरोप था कि वे राष्ट्र-विरोधी नारों और भाषणों से जुड़े थे।

महाराष्ट्र कार्यालय :– 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2–डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400053। विधि सलाहकार : मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष : 0522– 4078371 | Email : daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा